जनसत्ता

21 जून, 2019

उम्मीदें और चुनौतियां

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को आश्वस्त कराया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है और देश की सुरक्षा के लिए सरकार हरसंभव कदम उठाएगी। सत्रहवीं लोकसभा के पहले सत्र के मौके पर संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने आंतरिक व बाह्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार, कालेधन, सूखा, जल संकट जैसे मुद्दों पर सरकार के अब तक के प्रयासों और भावी योजनाओं को सामने रखा है। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी इस बात का संकेत है कि जनता ने सरकार के काम और उपलब्धियों पर मुहर लगाई है और उसे सरकार से उम्मीदें काफी हैं। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही सरकार की सफलता है। साथ ही चुनाव में जो वादे किए गए हैं, उन्हें पूरा करना चुनौती भी है। राष्ट्रपति का अभिभाषण यों एक तरह से रस्म अदायगी ही होता है, लेकिन देश के नागरिकों के लिए इसकी अहमियत इसलिए है कि सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में राष्ट्रपति बताते हैं। वे देश के प्रथम नागरिक हैं, लोकतंत्र में सर्वोच्च पद पर ही नहीं, बल्कि उसके संरक्षक भी हैं। इसलिए उनका कहा सरकार को कहीं न कहीं जिम्मेदारियों से बांधता है।

राष्ट्रपति ने अभिभाषण में सबसे ज्यादा जोर देश की सुरक्षा और आर्थिकी से जुड़े पहलुओं पर दिया है। सुरक्षा पर इसलिए कि पिछले कुछ समय में देश को आंतरिक और बाह्य दोनों ही मोर्चों पर गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इस साल फरवरी में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले ने देश की सुरक्षा के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने को मजबूर कर दिया था और आतंकियों के ठिकानों पर हवाई हमले जैसी कार्रवाई की गई थी। राष्ट्रपति ने सरकार के कदमों की सराहना करते हुए कहा कि पुलवामा हमले के बाद हवाई हमलों से आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर भारत ने अपने इरादों और क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि नक्सलवाद और आतंकवाद से निपटने में भी सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। घुसपैठ भी एक बड़ी समस्या है और यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गई है। घुसपैठ रोकने के लिए सीमा सुरक्षा को मजबूत बनाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने सरकार की विदेश नीति और प्राथमिकताओं को भी गिनाया। इसके अलावा तीन तलाक, हलाला जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने और महिला सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। महिला सुरक्षा का मुद्दा काफी संवेदनशील रहा है और आए दिन की घटनाएं बता रही हैं कि सरकारें इस मामले में नाकाम ही साबित हो रही हैं।

कालेधन और भ्रष्टाचार जैसी गंभीर समस्या पर भी राष्ट्रपति ने सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने हैं और यह मुश्किलों भरा काम है। सरकार का लक्ष्य अगले पांच साल में भारत को पांच अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का है। इसके लिए आर्थिक सुधार, कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, उद्यमियों को बिना गारंटी के कर्ज देने, जीएसटी को और सरल बनाने जैसे काम किए जाएंगे। राष्ट्रपति ने रोजगार सृजन को सरकार के एजेंडे में ऊपर बताया है। सरकार इन सब लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या करती है, इसकी झलक आगामी बजट में देखने को मिल सकती है। राष्ट्रपति ने सूखे के खतरे और बढ़ते जल संकट की बात भी की। राजग सरकार के सामने अब बड़ी चुनौती तो यह है कि पिछले कार्यकाल में शुरू किए गए कामों को उसे अब तेजी से बढ़ाना होगा, तभी विकास के अपेक्षित लक्ष्य हासिल हो पाएंगे।

पहाड़ पर पताका

दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंच कर पताका फहराना पर्वतारोहियों के लिए बड़ी उपलब्धि होती है। वहां पहुंचने के लिए पर्वतारोही वर्षों अभ्यास करते हैं। मगर उनमें से बहुतों का एवरेस्ट पर पहुंचने का सपना पूरा नहीं हो पाता। हालांकि अब पर्वतारोहण के लिए इतने तरह के साधन उपलब्ध हो गए हैं, प्रशिक्षण और तकनीक में इतना विकास हुआ है कि हर साल एवरेस्ट पर पहुंच कर पताका फहराने वालों की तादाद कुछ बढ़ी हुई दर्ज होती है। इस साल इस मौसम में रिकार्ड तोड़ आठ सौ पचासी लोग एवरेस्ट पर पहुंचे। पिछले साल आठ सौ सात लोग पहुंचे थे। इस साल वहां अधिक संख्या में लोगों के पहुंचने की वजह से भीड़भाड़ काफी हो गई थी, जिसकी वजह से रास्ता थम गया था। एवरेस्ट पर बढ़ी भीड़ और थमी रफ्तार की खबरें दुनिया भर में सुर्खियां बनी थीं। निस्संदेह इस दुर्गम चोटी पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना बड़ी कामयाबी है। मगर वहां तक पहुंचने में हर साल जिस तरह कुछ पर्वतारोही अपनी जान गंवा बैठते हैं, उसे लेकर चिंता स्वाभाविक है।

कुछ साल पहले तक एवरेस्ट पर चढ़ना साहसिक खेल का हिस्सा हुआ करता था, पर अब यह रोमांच का रूप लेता जा रहा है। एवरेस्ट पर पहुंच कर पहाड़ों की सुंदरता को निहारना निस्संदेह जीवन का अद्भुत अनुभव होता होगा। इसके अलावा इनमें कई लोग ऐसे भी होते हैं, जो बर्फीली चोटियों पर बसने के सपने को साकार करने की संभावनाएं तलाशने जाते हैं। मगर इस यात्रा में कठिनाइयां भी बहुत हैं। हाड़ जमा देने वाली ठंड में कई दिन बिताना सबके वश की बात नहीं। फिर बर्फीली आंधी-तूफान के खतरे हमेशा बने रहते हैं। कई बार ऐसा हो चुका है कि बर्फीली आंधी में दब कर अनेक पर्वातारोही अपनी जान से हाथ धो बैठे। फिर चढ़ाई के दौरान स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पैदा होने पर वहां इलाज की व्यवस्था करना कठिन है। इस साल हालांकि बर्फीली आंधी जैसी स्थिति नहीं आई, फिर भी सोलह पर्वतारोहियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। पिछले दिनों रास्ते में भीड़ अधिक जमा हो जाने के कारण पर्वतारोहियों को घंटों रुक कर इंतजार करना पड़ा। इसलिए इन खतरों को देखते हुए विशेषज्ञों ने मांग की है कि पर्वतारोहण के लिए अनुमति पत्र जारी करने में कटौती की जाए। साथ ही गाइडों के लिए कड़े मानदंड तय किए जाने चाहिए। देखना है, इसे कितनी गंभीरता से लिया जाता है।

दरअसल, जब से युवाओं में एवरेस्ट पर जाने का आकर्षण बढ़ा है, तब से कई प्रशिक्षण केंद्र इसकी तैयारी कराने लगे हैं। अब पर्वतारोहण संबंधी संसाधन जुटाना भी बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल नहीं रह गया है। इस तरह हर साल अब कुछ ऐसे उत्साही युवा भी एवरेस्ट पर पहुंचने का प्रयास करते देखे जाते हैं, जिन्हें पर्वतारोहण का पर्याप्त अनुभव नहीं है। फिर पर्वतारोहियों के साथ उनका साजो-सामान लेकर चलने वाले और गाइड भी जाते हैं। उनका प्रशिक्षण और योग्यता भी प्रश्नों से बाहर नहीं है। पर्वतारोहण के दौरान आपात स्थिति पैदा होने पर उससे पार पाने में कई लोग विफल साबित होते हैं। इसके अलावा भीड़भाड़ बढ़ने की वजह से एवरेस्ट पर भारी मात्रा में कचरा जमा हो रहा है, जिसके निष्पादन का अब तक कोई कारगर इंतजाम नहीं है। इसलिए एवरेस्ट चढ़ाई को अगर व्यावसायिक रूप देना है तो चीन, भारत और नेपाल सरकारों को मिल कर विशेषज्ञों की चिंता पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

कल्पमेधा

यह ज्यादा अक्ल की बात है कि हम ईश्वर की बातें कम करें- जिसे हम समझ-जान नहीं सकते और इंसानों की बातें ज्यादा करें- जिन्हें हम समझ-जान सकते हैं।

-खलील जिब्रान

चिकित्सा का बीमार तंत्र

संजय कुमार सिंह

कहने के लिए गरीब का बीमा है, पर इलाज के लिए अस्पताल नहीं हैं। और यह स्थिति कोई एक-दो साल में नहीं बनी है। स्वास्थ्य क्षेत्र शुरू से उपेक्षित है। इसलिए न सिर्फ अस्पताल, बल्कि डॉक्टर और डॉक्टरी की पढ़ाई भी अपर्याप्त है। महंगी है सो अलग। इसलिए शोर चाहे जितना मचे, हाल-फिलहाल होने वाला कुछ नहीं है।

बिहार में इस बार एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) जिसे स्थानीय बोलचाल में चमकी बुखार भी कहते हैं, से बड़ी संख्या में बच्चों की मौत और उस पर शोर-शराबा एक मुद्दा है और मौत के कारण तथा उन्हें दूर करने की कोशिशें या उससे निपटने के सरकारी प्रयास बिल्कुल अलग मसले हैं। दो साल पहले उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चों की मौत का मामला भले ही गैस सप्लाई बंद होने के कारण सुर्खियों में आया था, पर सच्चाई यही है कि ये मौतें गर्मी और लू के कारण लगभग ऐसी ही स्थितियों और लक्षणों के साथ हुई थीं। बिहार और उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में गर्मी के दौरान मूल रूप से लू लगने से मौत के मामले आम हैं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने पहले के वर्षों में हुई मौतों का हवाला देते हुए कह दिया था कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगस्त महीने में रोजाना औसतन अठारह से बाईस बच्चों की मौत पिछले सालों में भी हो चुकी है।

हकीकत तो यह है कि मौतें गर्मी के मौसम में लू और ज्यादा तापमान के कारण ही होती हैं। ऐसे में मौजूदा संसाधनों के भीतर अगर मरीजों की संख्या कम होती है तो बच्चे बच जाते हैं और मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है तो बचाना मुश्किल हो जाता है। कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसे में और बिहार-उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में छपरा, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर आदि जिलों के अलावा नेपाल के भी मरीज आते हैं। बीमारी से हालत खराब होने से पहले और सही चिकित्सा मिलने से कुछ बच्चे बच जाते हैं। कुछ इतने भाग्यशाली नहीं होते हैं कि बच सकें। इसका कारण न तो सिर्फ लीची खाना है, न ही ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होना। इतनी सारी मौतें किसी एक कारण से हो रही होतीं तो उन्हें दूर कर दिया गया होता। पर अभी वह भी स्पष्ट नहीं है।

असल में मरने वाले बच्चे बहुत ही गरीब परिवारों के होते हैं। उनकी आवाज न सत्ता सुनती है, न मीडिया। वैसे भी, बीमारी अगर बता कर आती होती तो शायद स्थिति दूसरी होती। जो रोज खाने-पहनने जैसी जरूरतें पूरी करने में लगा है, वह बिना बीमार हुए बीमार होने की क्यों सोचे? और जब बीमार हो जाता है तो न कोई उसकी सुनने वाला होता है और न वह खुद कुछ कर सकता है। सरकारी अस्पताल और मुफ्त में मिलने वाली सुविधा के भरोसे रहने वाले लोग अपने ऐसे अधिकार के लिए भी कहां लड़ पाते हैं!

बड़ी संख्या में मौत का कारण कुपोषित बच्चों का प्रतिरक्षण कम होना है। गर्मी में लू लगने या खाली पेट लीची खा लेने से मुमकिन है, समस्या गंभीर हो जाती हो। इससे बचने के उपाय सरकार को करने हैं। लोगों को यह बताया जाना चाहिए कि बच्चे को गर्मी से बचाएं, खाली पेट न रहने दें और अगर लू लग जाए तो कौन-सी दवाई तुरंत शुरू करें, इलेक्ट्रॉल का घोल पिलाएं और जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन सरकार इतना भर भी नहीं करती। गरीब, लगभग अनपढ़ लोग अगर बच्चों को धूप में नहीं निकलने दें और पीने के पानी का पर्याप्त बंदोबस्त हो तो बहुत-से लोग लू का शिकार होने से बच सकते हैं। पर अस्पताल में ज्यादातर लोगों ने कहा कि उन्हें यह जानकारी नहीं दी गई। जानकारी नहीं दिए जाने और जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचने के अपने कारण हैं। पर इतना तो स्पष्ट है कि इस बुनियादी और बहुत कम खर्चीले उपाय से जो बचाव हो सकता था, वह भी नहीं किया गया।

मुख्य रूप से इसका कारण सरकारी या राजनीतिक स्तर पर स्वास्थ्य को दी जाने वाली प्राथमिकता है। प्राथमिकता नहीं दी जाती है, यह तो साफ है और इस कारण बजट नहीं है और जब पैसे ही नहीं हैं तो कोई काम हो भी कैसे। इस तरह सब कुछ पैसे पर आकर रुक जाता है। अगर मीडिया में शोर न हो तो सरकार पर कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ना है, इसलिए सरकार वोट बटोरू काम में लगी रहती है और खर्च भी ऐसे ही काम में किए जाते हैं। वरना कोई कारण नहीं है कि 2014 में जो घोषणाएं हुई थीं, वे 2019 तक पूरी न हों और फिर उन्हें ही दोहरा देना सरकारी काम की इतिश्री है। बिना बजट के सरकार के लिए काम करना मुश्किल और खबरें रोकना अपेक्षाकृत आसान है। और इसीलिए यह बीमारी वर्षों से चली आ रही है।

बिहार में प्रति व्यक्ति बजट, डॉक्टर, अस्पताल के बेड और आइसीयू (सघन चिकित्सा इकाई) की संख्या भी चौंकाने वाली है। इसका असर यह है कि डॉक्टर और दूसरे कर्मचारी तो छोड़िए, दवाई की दुकानें तक पर्याप्त नहीं हैं। जो हैं उनके खुलने-बंद होने का समय निर्धारित है। इस कारण आपातस्थिति में बहुत साधारण-सी दवा भी उपलब्ध नहीं होती है और गरीब आदमी दुकान खुलने और दवा मिलने का इंतजार करता है, लेकिन तब तक मरीज की हालत ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। भारत में 11082 मरीजों के लिए औसतन सिर्फ एक डॉक्टर उपलब्ध है, 1844 मरीजों पर औसतन एक बेड और 55591 की आबादी पर एक सरकारी अस्पताल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के अनुसार एक हजार की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। यानी एक डॉक्टर पर दस गुने से भी ज्यादा बोझ। भारत का औसत इतना खराब है और बिहार तथा उत्तर प्रदेश की हालत इससे भी ज्यादा खराब है।

'द लैंसेट' की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता के मामले में एक सौ पनच्यानबे देशों की सूची में भारत एक सौ पैंतालीसवें स्थान पर है। वर्ष 1990 में हम एक सौ तिरपनवें पायदान पर थे। ताजा सूची 2016 के अध्ययन पर आधारित है। एक तरफ तो यह वास्तविक स्थिति है और दूसरी तरफ सरकार को वोट भी लेना होता है। इसलिए उसने कुछ करने के मुकाबले लोगों का बीमा करा देने का आसान रास्ता चुना और 'आयुष्मान भारत' नाम की स्वास्थ्य योजना लागू कर दी। कहने के लिए गरीब का बीमा है, पर इलाज के लिए अस्पताल नहीं है। और यह स्थिति कोई एक-दो साल में नहीं बनी है। स्वास्थ्य क्षेत्र शुरू से उपेक्षित है। इसलिए न सिर्फ अस्पताल, बल्कि डॉक्टर और डॉक्टरी की पढ़ाई भी अपर्याप्त है। महंगी है सो अलग। इसलिए शोर चाहे जितना मचे, हाल फिलहाल होने वाला कुछ नहीं है। एक तरफ अगर राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर में नया अस्पताल बनाने, बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और तीमारदारों के लिए धर्मशाला भी बनवाने की घोषणा की है तो तथ्य यह है कि स्वास्थ्य पर बजट पिछले साल के मुकाबले एक हजार करोड़ रुपए कम हो गया है। ऐसे में योजना कैसे पूरी होगी और पहले भी पूरी नहीं हुई है, ये दोनों ही तथ्य चिंताजनक हैं और आश्वासनों की हकीकत बताते हैं।

ऐसा नहीं है कि मौतें कभी-कभी ही होती हैं। सच तो यह है कि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2002 से 2018 के बीच करीब सात हजार बच्चों में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम पाया गया और इसकी वजह से दो हजार बच्चों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार का सबसे पहला मामला साल 1995 में सामने आया था और तब से लेकर आज तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। इंसेफेलाइटिस की समस्या सिर्फ बिहार में नहीं है। उत्तर प्रदेश और बंगाल भी इससे प्रभावित हैं। इसकी बड़ी वजह कुपोषण है। ऐसे में इस समस्या को अकेले राज्य सरकारों पर नहीं छोड़ा जा सकता। इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर काम करने की जरूरत है।

आधुनिकता के पैमाने

सुभाष चंद्र लखेड़ा

दुनिया मेरे आगे

इस पृथ्वी पर अपने उद्भव के तुरंत बाद से ही मनुष्य के रहन-सहन के तौर-तरीकों और उसकी सोच में परिवर्तन होते रहे हैं, लेकिन तब से लेकर पचास-साठ वर्ष पहले तक ऐसे परिवर्तनों की गति बहुत धीमी रही। नतीजतन, एक लंबे समय तक मनुष्य उन मानसिक दुविधाओं से मुक्त रहा जो आज नित नई जानकारियों की वजह से पैदा हो रही हैं। पिछले कुछ दशकों में ज्ञान-विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुई आशातीत प्रगति के कारण मनुष्य के रहन-सहन में ही नहीं, बल्कि उसकी सोच में भी व्यापक बदलाव आया है। यह बदलाव इतनी तेजी से हो रहा है कि सदियों से चली आ रही सामाजिक मान्यताओं, परंपराओं, रीति-रिवाजों और मानवीय मूल्यों को आधुनिकता के नाम पर बिना कोई सोच-विचार किए नकारा जा रहा है। हालांकि कुछ ऐसी जड़ परंपराओं और रीति-रिवाजों को खत्म हो ही जाना चाहिए, जिन्हें मानवीयता और बराबरी आधारित जीवन के विरुद्ध कहा जा सकता है।

बहरहाल, किसी भी प्रगतिशील मनुष्य के लिए यह निहायत जरूरी है कि वह वर्तमान में जीए। तभी उसका सर्वांगीण विकास हो सकता है। दरअसल, हरेक दौर की अपनी अपेक्षाएं और आवश्यकताएं होती हैं। वर्तमान दौर का मनुष्य अपने पूर्वजों का हमराही चाहते हुए भी नहीं रह सकता है। आज उसे जिन समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है, उनकी उसके पूर्वजों ने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। इसलिए आज के मनुष्य के अंदर इतना लचीलापन अवश्य होना चाहिए कि वह नए विचारों को किसी मानसिक दबाव या कुंठा का शिकार हुए बिना अपना सके।

गौरतलब है कि जनसंचार माध्यमों में हुई प्रगति के कारण आज के मनुष्य के सामने सूचनाओं का अंबार लग गया है। उसके पास अब अपना भला-बुरा सोचने के लिए समय नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वह इस पृथ्वी पर सिर्फ कार्य निष्पादन के लिए आया है और एक मनुष्य के रूप में उसकी कोई अन्य उपयोगिता नहीं है। वह सिर्फ एक संसाधन है और उसकी भूमिका और उपयोगिता का निर्णय किसी और को करना है। बढ़ते हुए उपभोक्तवाद ने इस स्थिति को विकट बना दिया है। आज का मनुष्य अपनी वेशभूषा और आहार-सूची तय करने का अधिकार तक खो चुका है। दरअसल, आज सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आधुनिकता का अर्थ क्या है! कहीं ऐसा तो नहीं है कि आधुनिकता के नाम पर हम उन मूल्यों को त्यागते जा रहे हों, जिनकी वजह से हमें प्रकृति की सर्वोत्तम रचना कहलाने का हक हासिल हुआ।

आधुनिकता पर चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है कि इसे विचारों के रूप में नहीं, बल्कि फैशन के रूप में अपनाया जा रहा है। अधिकतर लोगों के लिए आधुनिकता का अर्थ नए फैशन के कपड़े पहनना और घर को विलासिता की वस्तुओं से भरना है। ऐसे लोग आधुनिकता को एक ऐसी वस्तु समझते हैं, जिसे पर्याप्त कीमत देकर कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। खेद की बात है कि हमने अपने समाज को आधुनिकता का वही अर्थ समझने दिया, जिसे कुछ स्वार्थी तत्त्व निज लाभ के लिए प्रचारित-प्रसारित करते रहते हैं। यही कारण है कि हमारे अधिकतर प्रौढ़ और युवाओं के लिए इसका अर्थ सिर्फ जींस पहनना, सिगरेट के छल्ले बनाते हुए किसी की जीवनशैली का उपहास करना और अंग्रेजी फिल्मों की अधकचरी समीक्षा करना है। सच तो यह है कि आधुनिकता का संबंध न तो 'किस मी नॉट' की चेपी लगी जींस-पैंट पहनना है और न ही मुंह को गोल बना कर कंधे उचका कर अंग्रेजी बोलते हुए शराब पीकर कमरतोड़ नृत्य करना है। इसका अर्थ तो उन विचारों को अपनाने से है जो हमारे सामाजिक जीवन के लिए प्राणवायु की भूमिका निभाते हैं और जो हमें एक प्रगतिशील देश के सजग नागरिक होने की योग्यता प्रदान करते हैं।

गौरतलब है कि आधुनिक दिखने और आधुनिक होने में जमीन-आसमान का अंतर है। बाप-बेटे का साथ बैठ कर शराब पीना, मां-बेटी का किटी पार्टियों में जुआ खेलना और बड़े-बुजुर्गों द्वारा दिए जाने वाले सलाह-मशविरों का मजाक उड़ाना जैसे कार्यों को आधुनिकता से जोड़ना दिमागी दिवालियापन ही है। आजकल हमारे युवा वर्ग का एक तबका भ्रमवश यह समझ बैठा है कि अब तक चली आ रही सामाजिक वर्जनाओं की अनदेखी करना ही आधुनिकता है। इसी धारणा का शिकार बने युवा वाहनों, पार्कों, बाजारों, सिनेमाघरों और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर अपने प्रेम का प्रदर्शन करते नजर आते हैं। दिखावे की आधुनिकता ने हमारे विचारों की बुनियाद को कमजोर करने के साथ-साथ हमारी मौलिक चिंतन-मनन की क्षमताओं को भी कुंद कर दिया है। आधुनिकता का वास्तविक अर्थ न समझ पाने की वजह से आज हमारे देश में कई तरह की सामाजिक बुराइयां और विकृतियां पनपती जा रही हैं।

दरअसल, आधुनिकता का अर्थ है वर्तमान संदर्भ में अपनी और समाज की जरूरतों को पहचानना। वर्तमान में जीते हुए भविष्य को संवारने की शक्ति अर्जित करना और एक ऐसी जीवनशैली को अपनाना जो दिवास्वप्नों और ढोंग-पाखंड से पूरी तरह मुक्त हो। अगर हमारे समाज में बराबरी आधारित बर्ताव सोच के स्तर पर नहीं घुली हो, तो वह आधुनिकता सिर्फ दिखावे की होगी।

कैसे रहबर

एक्यूट इनसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) यानी चमकी बुखार से बिहार में हाहाकार मचा है। इस जानलेवा बीमारी से अब तक सूबे में 141 से ज्यादा मासूम बच्चों ने दम तोड़ दिया है। यह कोई नई बीमारी नहीं है बल्कि इससे पहले भी मुजफ्फरपुर में बच्चे इससे प्रभावित हो चुके हैं। बीमारी की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य सेवा की चिंता सरकार को न तो आज है न, पहले रही है। केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ राजग सरकार के सांसद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तक- सब अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए तरह-तरह के बयानों से जनता को दिग्भ्रमित करने में लगे हैं। कोई लीची को बहाना बना रहे हैं तो कोई वर्षा न होने को बीमारी का कारण बता रहे हैं। एक ओर मां के सामने बच्चे दम तोड़ रहे हैं तो दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोते हुए चिंतन करने में लगे थे। सुशासन बाबू नींद से तब जागे जब सैकड़ों बच्चे काल के गाल में समा गए। प्रचंड बहुमत पाने वाले भाजपा, जद (एकी) और लोजपा नेताओं को अपने प्रदेश के नौनिहालों की तनिक भी चिंता होती तो स्वास्थ्य सेवा के मुद्दे पर निरर्थक ब्यानों के जरिए सरकार का बचाव करते नजर नहीं आते।

हास्यास्पद है कि चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों के बारे में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की चिंता से कोसों दूर उसके स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने मीडिया की मौजूदगी में विश्व कप क्रिकेट के दौरान भारत-पाक मैच का स्कोर जानने में रुचि ले रहे थे। अफसोसनाक है कि कुछ मीडिया एंकर सरकार की विफलता पर सवाल उठाने के बजाय विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक नौटंकी बता कर उसे रोगियों की सेवा करने और अस्पताल जाकर सफाई करने की नसीहत देते हैं। दुखद है कि मीडियाकर्मी बार-बार डॉक्टरों को कोसने से भी बाज नहीं आ रहे। उन्हें कौन बताए कि सुविधाएं उपलब्ध करना सरकार की जिम्मेदारी है न कि डॉक्टर्स या विपक्ष की। सवाल है कि लोगों ने वोट स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दे पर नहीं दिया था तो फिर आज उन नेताओं से इन मुद्दों पर सवाल भी किस मुंह से पूछे?

लोकतंत्र में नेताओं की मनमानी इतनी बढ़ जाए कि जनहित के मुद्दे पर सोचने के लिए उनके पास समय नहीं हो तो फिर यकीनन आमजन को गहन चिंतन-मनन की आवश्यकता है।

● *मंजर आलम , रामपुर डेहरू, मधेपुरा, बिहार*

नशे का जाल

इन दिनों अब पंजाब के साथ-साथ हिमाचल और हरियाणा के युवाओं में भी नशे की लत बढ़ती जा रही है। नशे ने बड़ी संख्या में घर उजाड़ कर रख दिए हैं। नशाखोरी का इलाज करवाने वालों की बढ़ती संख्या से इस समस्या की गंभीरता का पता चलता है। इस संख्या में पिछले दस सालों में दस गुना वृद्धि हुई है। कभी इन तीनों राज्यों में दूध और घी की नदियां बहा करती थीं और कहां अब शराब की बाढ़ आई हुई है जो युवाओं को अपने साथ बहा कर ले जा रही है।

शराब के अलावा अन्य अधिकतर नशीले पदार्थ इन तीनों राज्यों में पाकिस्तान से आते हैं लेकिन इन्हें फैलाने वाले हमारे अपने ही लोग हैं, जिनमें पुलिस और अन्य विभागों के कर्मचारी-अधिकारी भी शामिल हैं। इस सबको देखते हुए सरकार को कड़े फैसले लेने होंगे और जल्द से जल्द नशा तस्करों पर नकेल कसनी होगी।

● *राघव जैन, जालंधर*

नाहक विरोध

एक देश, एक चुनाव पर आयोजित सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों का भाग न लेना खलने वाला है। यह मुद्दा राष्ट्रहित में होकर अर्थव्यवस्था से भी संबंधित है। ऐसे सर्वहिताय मुद्दे पर अपनी राय व सुझाव देना विपक्ष का कर्तव्य होता है ताकि सभी बिंदुओं पर विचार कर किसी सर्वमान्य हल पर सहमति बनाई जा सके। सरकार चाहे किसी भी दल की हो, सकारात्मक मुद्दों पर विपक्ष को सहयोग देना जरूरी है। ऐसे मुद्दे पर आयोजित बैठक का विरोध / बहिष्कार लोकतंत्र के हित में नहीं कहा जा सकता है।

● *हेमा हरि उपाध्याय, खाचरोद, उज्जैन*

योग बनाए निरोग

ओशो के अनुसार, 'योग धर्म, आस्था और अंधविश्वास से परे एक सीधा प्रायोगिक विज्ञान है। यह जीवन जीने की कला है, एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। एक पूर्ण मार्ग है- राजपथ। दरअसल, धर्म लोगों को खूंटे से बांधता है और योग सभी तरह के खूंटों से मुक्ति का मार्ग बताता है।' भारत के धर्म, संस्कृति और धरोहर ने विश्व को बहुत कुछ ऐसा दिया है जो इंसान को अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर करता है। इन्हीं में से एक है योग विधि, जिसे अपना कर इंसान तन और मन से स्वस्थ होता है। योग मात्र शरीर को दुरुस्त नहीं करता, बल्कि मानसिक तौर पर भी स्वस्थ बनाता है, सकारात्मक सोच को बढ़ाता है और इंसान का प्रकृति से भी तालमेल बढ़ाता है।

आज विश्वभर में बहुत से लोगों का ऐसी बीमारियों, जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की हो सकती हैं, ने जीना दुश्वार किया हुआ है। आज की भागदौड़ और भौतिकवाद में इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि अपने शरीर की तरफ जरा ध्यान नहीं देता और बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। अगर लोग योग को अपना लें तो अपने शरीर को चुस्त-दुरुस्त रख सकते हैं। योग के महत्त्व को समझते हुए 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने को हरी झंडी दे दी थी। योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना भारत के लिए गर्व की बात है। यहां यह कहना भी उचित होगा कि जहां एक तरफ भारत ने दुनिया को योग की राह पर अग्रसर करके निरोग रहने का मंत्र दिया, वहीं दूसरी तरफ भारत के लोग योग से किनारा करके कई जानलेवा बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। देश के हरेक नागरिक को योग से जुड़ना चाहिए। खासतौर पर युवाओं को योग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन यह भी खयाल रखना होगा कि योग तभी निरोग बनाएगा जब उसके साथ-साथ खानपान और जीवनशैली में भी सुधार किया जाएगा।

● *राजेश कुमार चौहान, जालंधर*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com